No: Coord-14/38/2018-COORD Sec Government of India Ministry of Development of North Eastern Region

Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road, New Delhi-110011. Dated 29th November, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Monthly summary of principal activities undertaken and important decisions taken during the month of August, 2021 in respect of Ministry of Development of North Eastern Region.

The undersigned is directed to refer to Cabinet Secretariat's D.O. letter No.1/26/2018-Cab. dated 30th May, 2018 from Shri Rajesh Bhushan, Additional Secretary, Cabinet Secretariat on the subject mentioned above.

The monthly summary pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region for the month of August , 2021 (both in Hindi & English) is hereby circulated for information.

> (Jaya Shah) Under Secretary to the Govt. of India Tel. 23022025

Encl. As above.

To

All Members of the Council of Ministers.

Copy with enclosure also forwarded to:

- The Secretary to the Hon'ble President, Rashtrapati Bhawan, New Delhi. i.
- The Secretary to the Hon'ble Vice President, No.5 Maulana Azad Road, New ii. Delhi.
- PPS to The Vice Chairman, NITI Aayog, NITI Bhawan, New Delhi. iii.
- The Secretaries to the Government of India.
- Ms. Rachna Shah, Joint Secretary, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.

Copy to:

- i. Additional Secretary & Financial Adviser (SRK)/Sr. Economic Adviser(KVP)/Joint Secretary(SE)/ Joint Secretary (RS)/ Joint Secretary(AC)/ Statistical Adviser (CS)/, Ministry of DoNER
- ii. Director (LH)/ Director (UK)/ Director(PA)/Superintending Engineer (GSM)/ Deputy Secretary (NS)/Deputy Secretary(PV)/Deputy Secretary(VKB)/ Deputy Secretary(HP)/Deputy Secretary(SDM), Ministry of DoNER
- iii. Senior Technical Director, NIC, Ministry of DoNER for uploading on the website of the Ministry.
- iv. PPS to Secretary, DoNER.

भारत सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

अगस्त, 2021 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रमुख गतिविधियों का मासिक सारांश।

- 1. महीने के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख गतिविधियां
- 1.1 नीति आयोग के साथ साझेदारी में और यूएनडीपी इंडिया की तकनीकी सहायता से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए "पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक एवं डैशबोर्ड, 2021-22" विकसित किया है। इसका शुभारंभ माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री; उपाध्यक्ष, नीति आयोग; माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री द्वारा नीति आयोग में 26 अगस्त, 2021 को किया गया। इंडेक्स और डैशबोर्ड में राज्यवार, जिलेवार और एसडीजी-वार तुलनीयता के फीचर्स हैं। यह सूचकांक 15 एसडीजी लक्ष्यों को कवर करता है (क्योंकि दो लक्ष्य यानी लक्ष्य 14-जल के नीचे जीवन और लक्ष्य 17-लक्ष्यों के लिए साझेदारी प्रासंगिक नहीं हैं) और इस क्षेत्र के जिलों की रैंकिंग करता है।
- 1.2 दिनांक 18 अगस्त, 2021 को सीसीईए ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सीपीएसई उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामेक) के पुनरुद्धार के लिए 77.45 करोड़ रुपये (निधि आधारित सहायता के लिए 17 करोड़ रुपये और गैर-निधि आधारित सहायता के लिए 60.45 करोड़ रुपये) के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। पुनरुद्धार पैकेज से नेरामेक को विभिन्न नवीन योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी, जैसे बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करना, किसानों को समूहों में प्रशिक्षण, जैविक बीज और उर्वरक, पोस्ट हार्वेस्टिंग सुविधाएं तािक विश्व बाजार में पूर्वोत्तर के किसानों के उत्पादों को कार्यक्रमों में भागीदारी, जीआई उत्पादों के पंजीकरण आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सके। नेरामेक के पुनरुद्धार के कार्यान्वयन के बाद कृषि क्षेत्र, परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन क्षेत्र, संभारतंत्र, सोर्टिंग और ग्रेडिंग और मूल्य वर्धन, उद्यमिता और विपणन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार का सृजन होगा।
- 1.3 माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी) ने माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (श्री बीएल वर्मा) के साथ विभिन्न माननीय केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला शुरू की है तािक उनके संबंधित मंत्रालय/विभाग से पूर्वोत्तर राज्यों के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके । इस श्रृंखला में, 12-08-2021 को, उन्होंने माननीय रेल और दूरसंचार मंत्री से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम की प्रमुख राजधानी रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं और पूर्वोत्तर में प्रमुख दूरसंचार परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
- 1.4 दिनांक 27 अगस्त, 2021 को माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) के साथ माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी) ने माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर) से पाम ऑयल, बांस और जैविक बागवानी के समग्र विकास के लिए पूर्वोत्तर में चिन्हित क्षेत्रों में कृषि बागवानी क्षेत्र के विकास का रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से भेंट की । बैठक के दौरान कृषि एवं

किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तत्कालीन सचिव और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक के दौरान माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापक कवरेज के साथ हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय खाद्य तेल/ऑयल पाम मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री से हस्तक्षेप करने और पूर्वोत्तर में अन्य योजनाओं यानी पीएमकेएसवाई, पीएमएफबीवाई, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के कार्यान्वयन की गित बढ़ाने और उपलब्ध बजटीय संसाधनों के भीतर उपयुक्त योजनाओं को डिजाइन करने के लिए कदम उठाने की मांग की।

- 1.5 दिनांक 31 अगस्त, 2021 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ दोनों माननीय केंद्रीय मंत्रियों की सह-अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की (वीसी के माध्यम से) संयुक्त बैठक हुई। बैठक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती को बढ़ाने, ऑयल पाम के निष्कर्षण और आगे प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों की स्थापना, जैविक खेती के विकास, कोल्ड स्टोरेज आदि जैसे बुनियादी ढांचे की स्थापना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मिजोरम राज्य सरकारों के माननीय मुख्यमंत्री, मणिपुर, नागालैंड राज्य सरकारों के माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय पर्यटन और नागर विमानन मंत्री, सिक्किम, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तत्कालीन सचिव, सचिव एनईसी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन संगठनों के प्रमुख और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के विका
- 1.6 एनईएसआईडीएस के तहत मंजूरी के लिए सिक्किम राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 18-08-2021 को अंतर-मंत्रालयी सिमिति (आईएमसी)/एनईएसआईडीएस सिमिति की 30वीं बैठक आयोजित की गई थी। सिक्किम सरकार के मुख्य सिचव ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में आईएमसी/एनईएसआईडीएस सिमिति द्वारा 5.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एनईएसआईडीएस के तहत मंजूरी के लिए "बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट (बीडब्ल्यूएम) प्रणाली और हाई फ्लो नेज़ल ऑक्सीजन (एचएफएनओ) प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए उपकरणों की खरीद" संबंधी परियोजना की सिफारिश की गई।
- 1.7 दिनांक 03.08.2021 को, नेडफी को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए योजना के निर्माण/योजना को जारी रखने संबंधी मूल्यांकन के लिए एसएफसी की बैठक उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एसएफसी ने नेडफी के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई और माइक्रोफाइनेंस क्षेत्रों को रियायती ऋण लिंकेज प्रदान करने के लिए 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित करने की सिफारिश की है।
- 1.8 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय/एनईसी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को 164.53 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं:
 - अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में आलो टाउनशिप में जल आपूर्ति में वृद्धि

- ii. मेघालय में किमी 8/00 (लाइत्तीरा गांव) से किमी 15/500 (किनरेम फाल्स) तक मावसमाई-शैला सड़क का उन्नयन
- iii. अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुभानसारी जिले में किमिन से दोलुंगमुख तक 33केवी एस/सी ट्रांसिमशन लाइन का निर्माण और तानियो गांव में 2X5 एमवीए, 33/11 केवी सब-स्टेशन का निर्माण
- iv. असम में उदलगुड़ी ग्रामीण सड़क डिविजन में उदलगुड़ी सापेखैती भक्तपाड़ा सड़क का सुधार
- v. मावशिनरूत से हाहीम (अथियाबाड़ी) सड़क तक राज्य सड़क का मध्यवर्ती लेन में उन्नयन
- vi. मेघालय में मुकरोह-उमस्पर को जोड़ने वाली जेरिकिंडेंग रोड (15.517 किमी)
- vii. हेंगबुंग, सेनापति जिले, मणिपुर में अकादिमक ब्लॉकों का निर्माण
- viii. दो राज्यों में सड़क परियोजनाएं अर्थात् मणिपुर [तुपुल से बिष्णुपुर (एमएन-06-सीडब्ल्यू- 1); थौबल से कसोम खुल्लेन और मिजोरम [सेरछिप से बुअरपुई (एमजेड-02)।
- 1.9 मंत्रालय द्वारा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में एनईएसआईडीएस के तहत 50.77 करोड़ रुपये की 05 कोविड विशिष्ट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।
- 1.10 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से मिले समर्थन के आधार पर आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने 27.08.2021 को हुई अपनी 119वीं बैठक में बाह्य वित्तपोषण के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने/अनुमोदित करने का निर्णय लिया है:

त्रिपुरा सरकार

- (क) अगरतला शहर शहरी विकास परियोजना के लिए क्षमता विकास- टीए सुविधा के लिए (एडीबी से ऋण सहायता)।
- (ख) त्रिपुरा के राज्य राजमार्गों का पक्की पटरी के साथ डबल लेन के रूप में सुधार और चौड़ीकरण के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं पीआरएफ/टीए सुविधा के तहत (चरण-1) (एडीबी से ऋण सहायता)

मेघालय सरकार

- (क) मेघालय प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ईसीडी) मिशन (एडीबी से ऋण सहायता)
- (ख) नोकरेक नेशनल पार्क (एनएनपी), मेघालय में प्राकृतिक इतिहास और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के लिए भारत-जापान परियोजना (जेआईसीए से ऋण सहायता)

मणिपुर सरकार

मणिपुर में समुदाय आधारित वाटरशेड विकास के माध्यम से आजीविका बढ़ाना (जेआईसीए से ऋण सहायता)

Government of India Ministry of Development of North Eastern Region ***

Monthly summary of principal activities of and important decisions taken in the Ministry of Development of North Eastern Region during the month of August, 2021.

1. Important policy decisions taken and major activities during the month

- 1.1 MDoNER in partnership with NITI Aayog and with technical support from UNDP India has developed the "North Eastern Region District SDG Index & Dashboard, 2021-22" for eight NE States. It was launched by Hon'ble Minister of DoNER; Vice –Chairperson, NITI Aayog; Hon'ble Minister of State, MDoNER on 26th August, 2021 in NITI Aayog. The index and the dashboard have features of state-wise, district-wise and SDG-wise comparability. The index covers 15 SDGs (as two goals i.e. Goal 14-Life below Water and Goal 17-Partnership for the Goals are not relevant) and ranks the district of the region.
- 1.2 On 18th August, 2021, CCEA, approved a revival package of Rs.77.45 crore (Rs. 17 crore towards fund based support and Rs.60.45 crore towards non-fund based support) for revival of North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited (NERAMAC), a CPSE under the administrative control of MDoNER. Revival package will help NERAMAC to implement various innovative plans namely providing better farming facilities, training to farmers in clusters, organic seeds and fertilizer, post harvesting facilities in order to promote the products of NE farmers in the world market through participation in events, registration of GI products etc. After the implementation of revival of NERAMAC, employment will be generated both directly and indirectly in farming sector, projects and events management sector, logistics, sorting and grading and value addition, entrepreneurship and marketing.
- 1.3 Hon'ble Minister of DoNER (Shri G. Kishan Reddy) along with Hon'ble MoS, MDoNER (Shri B.L. Verma) has started a series of meetings with various Hon'ble Union Ministers to discuss issues relating to the Development of NE States pertaining to their respective Ministry/Department. In this series, on 12.08.2021, they met Hon'ble Minister of Railways and Telecom to discuss issues related to major Capital Railway Connectivity Projects of Meghalaya, Manipur, Mizoram and Sikkim and the major Telecom projects in NER.

1.4 On 27th August 2021, Hon'ble Minister of DoNER (Shri G. Kishan Reddy) along with Hon'ble MoS, MDoNER (Shri B.L. Verma) met the Hon'ble Minister of Agriculture & Farmer's Welfare (Shri Narendra Singh Tomar) to lay down the Roadmap for Development of Agro-Horticulture Sector in the NER in areas identified for holistic development i.e. Palm Oil, Bamboo and Organic Horticulture. Secretary, Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare and the then Secretary, Ministry of DoNER and Senior Officials of Ministry of DoNER and Agriculture were also present during the meeting.

During the meeting Hon'ble Minister of DoNER sought intervention of the Agriculture Minister for taking forward the recently approved National Mission for Edible Oils/Oil Palm with comprehensive coverage of the North- East Region and steps to increase the pace of implementation of other schemes in NER i.e. PMKSY, PMFBY, Kisan Credit Card etc. and design suitable schemes within available budgetary resources.

- 1.5 On 31st August, 2021, a joint meeting (through VC) of MDoNER and MoA&FW, Co-Chaired by both Hon'ble Union Ministers was held with the Hon'ble Chief Ministers of North Eastern States to discuss the issues relating to holistic development of Agriculture Sector in North Eastern Region. During the meeting issues relating to increasing cultivation of Oil Palm in NER, setting up of industries related to extraction and further processing of Oil Palm, Development of Organic Farming setting up of infrastructure like cold storage etc. were discussed. Hon'ble Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare, Hon'ble MoS, MDoNER, Hon'ble CMs of State Government of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya & Mizoram, Hon'ble Deputy CMs of State Government of Manipur, Nagaland, Hon'ble Minister of Tourism and Civil Aviation, Sikkim, the then Secretary, MDoNER, Secretary NEC, Heads of Organizations under MDoNER and Senior Officers of MDoNER and MoA& FW also participated in the meeting.
- 1.6 The 30th meeting of Inter-Ministerial Committee (IMC)/NESIDS Committee was held on 18.08.2021 to discuss project proposal received from State Government of Sikkim for consideration for sanction under NESIDS. Chief Secretary of the Government of Sikkim co-chaired the meeting. In the meeting, the project 'Procurement of equipment for strengthening of Bio-medical Waste Management (BWM) system & High Flow Nasal Oxygen (HFNO) system' was recommended by IMC/NESIDS Committee for sanction under NESIDS at estimated cost of Rs.5.33 crore.
- 1.7 On 03.08.2021, SFC meeting for appraisal of formulation/continuation of scheme to provide interest free loans to NEDFi was held under chairmanship of Secretary,

MDoNER . SFC has recommended allocation of Rs.300 crore for the period 2021-22 to 2025-26 for providing concessional credit linkage to MSMEs and Microfinance sectors in the NER through NEDFi.

- 1.8 Funds amounting to Rs 164.53 cr. were released to the NE States under various Schemes implemented by MDoNER/NEC. This includes the following important projects:
- viii. Augmentation of Water Supply to Aalo Township in West Siang District, Arunachal Pradesh
 - ix. Upgradation of Mawsmai-Shella Road from km8/00 (Laittyra village) upto km15/500 (Kynrem falls) in Meghalaya
 - x. Construction of 33kV S/C Transmission line from Kimin to Dollungmukh & Construction of 2X5 MVA, 33/11 kV sub-station at Tanio village in Lower Subansari district in Arunachal Pradesh
- xi. Improvement of Udalguri Sapekhaity Bhakatpara Road in Udalguri Rural Road Division' in Assam
- xii. Upgradation to intermediate lane of State road from Mawshynrut to Hahim (Athiabari) Road
- xiii. Mukroh-Umspar linking Jrikyndeng Road (15.517 Km) in Meghalaya
- xiv. Construction of Academic Blocks at Hengbung, Senapati District, Manipur
- xv. Road projects in two States viz. Manipur[Tupul to Bishnupur (MN-06 -CW-1); Thoubal to Kasom Khullen and Mizoram [Serchhip to Buarpui (MZ-02).
- 1.7 05 COVID specific projects worth Rs.50.77 crore were sanctioned by the Ministry under NESIDS in the States of Manipur, Mizoram and Tripura.
- 1.8 Based on the support from MDoNER, the Screening Committee of Department of Economic Affairs in its 119th meeting held on 27.08.2021 has decided to pose/approve the following proposals for external funding:

Government of Tripura

(a) Capacity Development for the Agartala City Urban Development Project- for TA facility (loan assistance from ADB).

(b) Consultancy services for preparation of DPR for improvement and widening of State Highways of Tripura to double lane with paved shoulder, (Phase-1) under PRF/TA Facility (loan assistance from ADB).

Government of Meghalaya

- (a) Meghalaya Early Childhood Development (ECD) Mission (loan assistance from ADB)
- (b) Indo-Japan Project for Infrastructure for Promoting Natural History and Nature Conservation at Nokrek National Park (NNP), Meghalaya (loan assistance from JICA)

Government of Manipur

Enhancing Livelihoods through Community Based Watershed Development in Manipur (loan assistance from JICA)
